प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
कैबिनेट

09 सितंबर 2015 14:46 IST

स्वर्ण मुद्रीकरण योजनाओं का परिचय

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय बजट 2015-16 में घोषित गोल्ड मुद्रीकरण योजनाओं (जीएमएस) की शुरूआत के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

योजनाओं में संशोधन शुरू करने का उद्देश्य मौजूदा योजनाओं को उत्पादक उपयोग में लाने के लिए मौजूदा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है और मौजूदा योजनाओं के दायरे को देश में घरों और संस्थानों द्वारा आयोजित सोने को एकत्रित करना है। इस व्यवस्था के माध्यम से मांगे जाने वाले दीर्घकालिक उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है।

जीएमएस भारतीय रत्न और आभूषण क्षेत्र को लाभान्वित करेगा जो भारत के निर्यात में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में, रत्न और आभूषणों ने भारत के कुल निर्यात का 12 प्रतिशत गठित किया और सोने की वस्तुओं का मूल्य अकेले $ 13 बिलियन (अनंतिम आंकड़े) से अधिक था।

एकत्रित सोना आरबीआई के स्वर्ण भंडार को भी पूरक करेगा और सरकार की उधार लेने की लागत को कम करने में मदद करेगा।

संशोधित स्वर्ण जमा योजना (जीडीएस) और गोल्ड मेटल लोन (जीएमएल) योजना में केवल योजना दिशानिर्देशों में बदलाव शामिल हैं। सोने की कीमत में बदलाव का जोखिम गोल्ड रिजर्व फंड द्वारा बनाया जाएगा जो बनाया जा रहा है। सरकार को लाभ उधार लेने की लागत में कमी के मामले में है, जिसे गोल्ड रिजर्व फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

यह योजना भारत में घरों, ट्रस्टों और विभिन्न संस्थानों के साथ निष्क्रिय संपत्ति के रूप में बड़ी मात्रा में सोने को इकट्ठा करने में मदद करेगी और रत्न और आभूषण क्षेत्र को भर जाएगी। समय के साथ ही सोने की आयात पर देश की निर्भरता को कम करने की भी उम्मीद है। नई योजना में संशोधित जीडीएस और एक संशोधित जीएमएल योजना शामिल है।

संशोधित स्वर्ण जमा योजना

संशोधित जीडीएस के तहत संग्रह, शुद्धता सत्यापन और सोने का जमा:

331 आकलन और हॉलमार्किंग केंद्रों में से देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करेंगे, उद्देश्य के लिए सोने की शुद्धता के लिए संग्रह और शुद्धता परीक्षण 1 केंद्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी इस योजना का। ग्राहक द्वारा लाए जाने वाले न्यूनतम मात्रा में सोने को 30 अनाज पर सेट करने का प्रस्ताव है। सोने किसी भी रूप में हो सकता है (बुलियन या आभूषण)। इन केंद्रों की संख्या समय के साथ बढ़ने की उम्मीद है।

गोल्ड सेविंग्स अकाउंट:
संशोधित योजना में, केवाईसी मानदंडों के साथ लागू होने पर किसी भी समय ग्राहकों द्वारा गोल्ड सेविंग खाता खोला जाएगा। यह खाता सोने के ग्राम में अंकित होगा।

रिफाइनरों को सोने का स्थानांतरण:
संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र सोने को रिफाइनरों को भेज देंगे। रिफाइनर सोने को अपने बर्तनों में रखेंगे, जब तक कि बैंक खुद को पकड़ना पसंद न करें। रिफाइनर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, उन्हें पारस्परिक रूप से उनके द्वारा तय किए गए अनुसार बैंकों द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ग्राहक से शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बैंक एक त्रिपक्षीय में प्रवेश करेंगे रिफाइनर और संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्रों के साथ कानूनी समझौते जो उनके द्वारा इस योजना में उनके सहयोगी बनने के लिए चुने जाते हैं।

कार्यकाल:
संशोधित योजना के तहत जमा 1-3 साल की अल्पकालिक अवधि के लिए किया जा सकता है (एक वर्ष के गुणकों में रोल आउट के साथ); 5-7 साल की मध्यम अवधि की अवधि और 12-15 साल की लंबी अवधि की अवधि (समय-समय पर तय की गई)। एक निश्चित जमा की तरह, विकल्पों में से किसी एक में लॉक-इन अवधि की तोड़ने की अनुमति होगी और समयपूर्व रिडेम्प्शन (भाग निकासी सहित) पर जुर्माना होगा।

ब्याज दर:

अल्पकालिक अवधि के लिए किए गए जमा के लिए देय ब्याज दर की राशि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय पट्टे दरों, अन्य लागतों, बाजार स्थितियों आदि के आधार पर बैंकों द्वारा तय की जाएगी और सोने के ग्राम में अंकित की जाएगी। मध्यम और दीर्घकालिक जमा के लिए, समय-समय पर आरबीआई के परामर्श से ब्याज दर (और उनकी सेवाओं के लिए बैंक को भुगतान की जाने वाली फीस) सरकार द्वारा तय की जाएगी। मध्यम और दीर्घकालिक जमा के लिए ब्याज दर को जमा किए गए सोने के मूल्य के आधार पर रुपये में देय और देय होगा।

मुक्ति:

शॉर्ट-टर्म डिपॉजिट के लिए, ग्राहक को मूल जमा और ब्याज अर्जित करने के लिए रिडेम्प्शन का विकल्प होगा, या तो नकदी में (रिडेम्प्शन के समय प्रचलित कीमतों पर जमा सोने के वजन के बराबर रुपये में) या सोने में (जमा के रूप में सोने के वज़न के वजन), जो जमा करने के समय प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि ग्राहक विकल्प बदलना चाहेगा, तो उसे बैंक के विवेकानुसार अनुमति दी जाएगी। आंशिक मात्रा का रिडेम्प्शन (जिसके लिए एक मानक सोना बार / सिक्का उपलब्ध नहीं है) नकद में भुगतान किया जाएगा। मध्यम और दीर्घकालिक जमा के लिए, रिडेम्प्शन केवल नकद में होगा, जमा राशि के समय प्रचलित कीमतों पर जमा सोने के वजन के बराबर रुपये में।

उपयोग:

जमा सोने का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा:

- मध्यम और लंबी अवधि के जमा के तहत
  - नीलामी
  - आरबीआई गोल्ड रिजर्व की पुनर्पूर्ति
  - सिक्के
  - ज्वेलर्स को उधार देना
- अल्पकालिक जमा के तहत
  - सिक्के
  - ज्वेलर्स को उधार देना
- **कर छूट:** कर छूट, जीडीएस के तहत उपलब्ध उन के रूप में ही होता है जैसा लागू हो, पुर्नोत्थान जीडीएस में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जा,।
- **गोल्ड रिजर्व फंड:** सरकार के लिए वर्तमान उधारी लागत और मध्यम / दीर्घकालिक जमा के तहत सरकार द्वारा भुगतान ब्याज दर के बीच अंतर **गोल्ड रिजर्व फंड को** जमा किया जाएगा।

- **गोल्ड मेटल लोन योजना में सुधार हुआ**
- **गोल्ड धातु ऋण खाता:** एक गोल्ड धातु ऋण खाता, सोने की ग्राम में नामित, जौहरी के लिए बैंक द्वारा खोला जाएगा। अल्पकालिक विकल्प के तहत संशोधित जीडीएस के माध्यम से एकत्रित सोने को आरबीआई के मार्गदर्शन में बैंकों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर ऋण पर ज्वेलर्स को प्रदान किया जाएगा।

- **ज्वेलर्स को सोने की डिलीवरी:** जब सोने का ऋण स्वीकृत किया जाता है, तो ज्वैलर्स को रिफाइनरों से सोने की भौतिक डिलीवरी मिल जाएगी। बदले में, बैंक ज्वेलर्स के गोल्ड लोन खाते में आवश्यक प्रविष्टि करेंगे। बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज: जीएमएल पर लगाई गई ब्याज दर आरबीआई से मार्गदर्शन के साथ बैंकों द्वारा तय की जाएगी।

टेनोर: वर्तमान में जीएमएल का कार्यकाल 180 दिन है। यह देखते हुए कि सोने के जमा के लिए न्यूनतम लॉक-इन अवधि एक वर्ष होगी, अनुभव प्राप्त होने के आधार पर, जीएमएल के इस अवधि में भविष्य में फिर से जांच की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त संशोधन किए जा सकते हैं।

*****

एनडब्ल्यू / AKT / एसएच